International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

फरीदाबाद का औद्योगिक उदय और शहरीकरण : एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण (1947-2011)

डॉ० कुसुम लता
निर्देशिका, प्रोफेसर, आई.आई.एच.एस, इतिहास विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
e-mail : kusum@kuk.ac.in
प्रमोद
शोधकर्ता, पीएच० डी० (छात्र), इतिहास विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र(हरियाणा)
e-mail: parmodnigam@live.com

शोध-आलेख सार

यह शोध-पत्र हरियाणा राज्य के प्रमुख औद्योगिक नगर फरीदाबाद के औद्योगिक विकास और शहरीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है । अध्ययन का कालखण्ड 1947 से 2011 तक रखा गया है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद की औद्योगिक नीतियों, शरणार्थी पुनर्वास, नियोजित औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया गया है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने औद्योगिक विकास को आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रमुख आधार बनाया । इसी क्रम में फरीदाबाद को एक नियोजित औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया गया । 1950 के दशक में शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ-साथ यहाँ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना आरम्भ हुई, जिसने धीरे-धीरे इसे उत्तर भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया । इस शोध में फरीदाबाद के औद्योगिक विकास के साथ-साथ शहरी विस्तार, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक संरचना, श्रम प्रवासन तथा आधारभूत ढाँचे के विकास का भी अध्ययन किया गया है । अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली के समीप स्थित होने के कारण फरीदाबाद का औद्योगिक और शहरी विकास तीव्र गति से हुआ और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया । यह शोध-पत्र ऐतिहासिक स्रोतों, सरकारी रिपोर्टों, जनगणना आँकड़ों तथा विभिन्न विद्वानों के अध्ययनों के आधार पर फरीदाबाद के औद्योगिक

विकास की प्रकृति, कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करता है । अंततः यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि फरीदाबाद का विकास केवल औद्योगिक निवेश का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सरकारी नीतियों, भौगोलिक स्थिति, प्रवासी श्रम और शहरी नियोजन के संयुक्त प्रभाव का परिणाम था ।

मुख्य-शब्द : आर्थिक विकास, मशीन उपकरण, इंजीनियरिंग, वस्त्र, औद्योगिक विकास ।

परिचय

भारत के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया का विशेष महत्व रहा है । स्वतंत्रता के पश्चात देश ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाया, जिसके अंतर्गत औद्योगिक नगरों का विकास एक प्रमुख नीति के रूप में सामने आया । इस प्रक्रिया में कई नगरों का विकास हुआ, जिनमें फरीदाबाद का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ।

हरियाणा राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित फरीदाबाद भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण प्रारम्भ से ही व्यापार, उद्योग और परिवहन की दृष्टि से अनुकूल रहा है । स्वतंत्रता के बाद जब भारत को बड़े पैमाने पर शरणार्थी पुनर्वास और आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ा, तब फरीदाबाद को एक योजनाबद्ध औद्योगिक नगर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई ।

1950 के दशक में भारत सरकार और विभिन्न विकास एजेंसियों ने यहाँ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया । इसके परिणामस्वरूप यहाँ मशीन उपकरण, इंजीनियरिंग, वस्त्र, ऑटोमोबाइल सहायक उद्योग तथा लघु और मध्यम उद्योगों का तीव्र विकास हुआ । धीरे-धीरे फरीदाबाद उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक नगरों में शामिल हो गया ।

औद्योगिक विकास के साथ-साथ फरीदाबाद में तीव्र शहरीकरण भी हुआ। रोजगार के अवसरों के कारण देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ आए, जिससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई । इसके साथ ही आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य शहरी सुविधाओं का भी विस्तार हुआ ।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य 1947 से 2011 तक फरीदाबाद के औद्योगिक विकास और शहरीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया का अध्ययन करना है । इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार सरकारी नीतियाँ, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक निवेश और सामाजिक परिवर्तन ने मिलकर फरीदाबाद को एक छोटे कस्बे से एक बड़े औद्योगिक महानगर में परिवर्तित कर दिया ।

फरीदाबाद का 1947 से 1980 तक उदय एवं शहरीकरण

स्वतंत्र भारत के औद्योगिक इतिहास में फरीदाबाद का स्थान अत्यंत विशिष्ट है । हरियाणा राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित फरीदाबाद न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, बल्कि यह उत्तर भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक सशक्त केंद्र के रूप में उभरा है । 1947 के पश्चात जिस प्रकार भारत ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाए, उसी क्रम में फरीदाबाद को एक मॉडल औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया गया । यह विकास आकस्मिक नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक नियोजन, शरणार्थी पुनर्वास, औद्योगिक पूंजी निवेश और भौगोलिक अनुकूलता के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम था ।

फरीदाबाद की ऐतिहासिक जड़ें मुगल काल तक जाती हैं । इसका नामकरण शेख फरीद के नाम पर माना जाता है, जिन्होंने मुगल सम्राट जहाँगीर के काल में यहाँ एक सराय और व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी । यद्यपि यह क्षेत्र प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़ा था, फिर भी औपनिवेशिक काल तक यह मुख्यतः कृषि-प्रधान रहा । ब्रिटिश प्रशासन के दौरान यहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी । 1941 की जनगणना के अनुसार यह क्षेत्र ग्रामीण बहुल था और नगरीय सुविधाएँ नगण्य थीं ।

1947 में भारत विभाजन के परिणामस्वरूप पंजाब और सिंध से लाखों शरणार्थी विस्थापित हुए । दिल्ली के समीप होने के कारण फरीदाबाद को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त माना गया । तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे “न्यू इंडस्ट्रियल टाउन” के रूप में विकसित करने की योजना बनाई । उनका दृष्टिकोण केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं था; वे इसे आत्मनिर्भर औद्योगिक नगर के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जहाँ विस्थापित लोग स्वयं के श्रम और उद्यम से अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें ।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

1949 में फरीदाबाद विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉ० राजेंद्र प्रसाद ने की । इस बोर्ड का उद्देश्य योजनाबद्ध आवास निर्माण, आधारभूत ढाँचे का विकास और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देना था । “स्वयं सहायता मॉडल” के अंतर्गत शरणार्थियों को मकान निर्माण में सहभागी बनाया गया । लगभग 5,000 से अधिक आवास इकाइयाँ निर्मित की गईं, जिनमें श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लिए विशेष प्रावधान था ।

1951 की जनगणना में फरीदाबाद की जनसंख्या लगभग 28,000 दर्ज की गई, जो 1961 तक बढ़कर 1,23,000 से अधिक हो गई । यह वृद्धि सामान्य प्राकृतिक वृद्धि से कहीं अधिक थी और स्पष्ट रूप से पुनर्वास तथा औद्योगिक रोजगार का परिणाम थी । औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस काल में जूता निर्माण, इंजीनियरिंग और लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी गई । बाटा इंडिया तथा एस्कॉर्ट्स समूह जैसी कंपनियों की स्थापना ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की ।

1960 के दशक तक फरीदाबाद एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में पहचाना जाने लगा । 1965 तक लगभग 250 लघु और मध्यम उद्योग कार्यरत थे । इस औद्योगिक विस्तार ने श्रम प्रवास को आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ आए । यह प्रवास शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने वाला प्रमुख कारक बना ।

1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद फरीदाबाद के विकास को नई दिशा मिली । राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर रियायतें और भूमि आवंटन नीतियाँ अपनाईं । इसी काल में सेक्टर आधारित नियोजन प्रारंभ हुआ, जिसने इसे एक संगठित शहरी संरचना प्रदान की।

1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लगभग 2 लाख तक पहुँच गई थी । 1981 तक यह संख्या लगभग 4 लाख हो गई । यह वृद्धि दर्शाती है कि फरीदाबाद का औद्योगिक आकर्षण निरंतर बढ़ रहा था । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने हजारों रोजगार सृजित किए ।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

इस प्रकार 1947 से 1980 के प्रारंभिक दशक तक फरीदाबाद का विकास पुनर्वास-आधारित औद्योगिकरण का एक सफल उदाहरण बन चुका था। यहाँ सामाजिक पुनर्गठन, श्रम-आधारित आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं का समन्वय स्पष्ट दिखाई देता है ।

औद्योगिक संक्रमण, संरचनात्मक परिवर्तन और तीव्र शहरी विस्तार : 1980–1991)

1979 में फरीदाबाद को स्वतंत्र जिला घोषित किए जाने के पश्चात इसका प्रशासनिक महत्व और अधिक बढ़ गया । 1980 का दशक फरीदाबाद के इतिहास में वह कालखंड है जब यह पुनर्वास-आधारित औद्योगिक नगर से पूर्ण विकसित औद्योगिक केंद्र में रूपांतरित हुआ । इस अवधि में औद्योगिक संरचना, श्रम बाजार, नगरीय विस्तार और सामाजिक संरचनाकृसभी में गहरे परिवर्तन हुए । यदि 1950 और 1960 का दशक आधार निर्माण का था, तो 1980 का दशक औद्योगिक परिपक्वता और संरचनात्मक संक्रमण का काल कहा जा सकता है ।

1981 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद की जनसंख्या लगभग चार लाख के आसपास पहुँच चुकी थी । यह वृद्धि केवल प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह बड़े पैमाने पर श्रम प्रवास से प्रेरित थी । उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ आए । इस प्रवास ने फरीदाबाद की सामाजिक संरचना को बहु-क्षेत्रीय और बहुभाषिक स्वरूप प्रदान किया । औद्योगिक इकाइयों की बढ़ती संख्या ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल-तीनों प्रकार के श्रमिकों की माँग उत्पन्न की ।

1980 के दशक में फरीदाबाद की औद्योगिक संरचना मुख्यतः इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, विद्युत उपकरण, मशीन टूल्स, उपभोक्ता वस्तुएँ और रबर उत्पादों पर आधारित थी । सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की मध्यम और लघु इकाइयों का तीव्र विस्तार हुआ । लघु उद्योगों की संख्या 1990 तक लगभग 3,500 तक पहुँच गई थी । यह आँकड़ा इस बात का संकेत है कि फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था केवल बड़े उद्योगों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों ने भी रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर हरियाणा राज्य के औसत से अधिक रही । फरीदाबाद राज्य के औद्योगिक उत्पादन का लगभग एक-चौथाई से अधिक योगदान देने लगा था । दिल्ली की निकटता, राष्ट्रीय राजमार्ग से संपर्क, रेल नेटवर्क और बाद में विकसित होते परिवहन अवसंरचना ने इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की अवधारणा के अंतर्गत फरीदाबाद का महत्व और बढ़ गया, क्योंकि यह दिल्ली पर जनसंख्या और औद्योगिक दबाव को संतुलित करने का माध्यम बना।

औद्योगिक विस्तार के साथ नगरीय क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार भी हुआ। सेक्टर आधारित नियोजन के अतिरिक्त अनियोजित बस्तियों और श्रमिक कॉलोनियों का भी विकास हुआ । आवास की बढ़ती माँग के कारण निजी रियल एस्टेट गतिविधियाँ प्रारंभ हुईं । यद्यपि राज्य सरकार और विकास प्राधिकरण ने नियोजित सेक्टरों का निर्माण किया, फिर भी प्रवासी श्रमिकों के लिए पर्याप्त सस्ती आवास व्यवस्था का अभाव रहा । परिणामस्वरूप झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का विस्तार हुआ, जिसने शहरी नियोजन की चुनौतियों को जन्म दिया ।

1980 के दशक में सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे । कृषि-आधारित आजीविका लगभग समाप्तप्राय हो चुकी थी और अधिकांश कार्यबल औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में संलग्न था । पारंपरिक संयुक्त परिवार संरचना के स्थान पर नगरीय एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा । महिलाओं की श्रम सहभागिता भी बढ़ी, विशेषकर लघु उद्योगों और सेवा क्षेत्र में । इससे सामाजिक गतिशीलता और मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ ।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ । निजी विद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना ने स्थानीय युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान किए । औद्योगिक मांगों के अनुरूप तकनीकी शिक्षा का महत्व बढ़ा । स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की संख्या में वृद्धि हुई, जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास था ।

आर्थिक दृष्टि से यह काल संरचनात्मक संक्रमण का भी था । जहाँ प्रारंभिक दशकों में उद्योग मुख्यत: श्रम-प्रधान थे, वहीं 1980 के दशक में तकनीकी उन्नयन और

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

मशीनरी आधारित उत्पादन में वृद्धि हुई । इससे उत्पादकता में सुधार हुआ, किंतु साथ ही कुशल श्रमिकों की आवश्यकता भी बढ़ी । इस परिवर्तन ने श्रम बाजार को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया ।

1991 की जनगणना तक फरीदाबाद की जनसंख्या लगभग दस लाख के निकट पहुँच चुकी थी । यह वृद्धि केवल औद्योगिक आकर्षण का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह शहरी जीवनशैली, शिक्षा और रोजगार अवसरों के विस्तार से भी जुड़ी थी । कुल कार्यरत जनसंख्या का लगभग 70 से 75 प्रतिशत भाग औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में संलग्न था, जो इसे पूर्णतः औद्योगिक नगर की श्रेणी में स्थापित करता है ।

हालाँकि इस तीव्र औद्योगिक विस्तार के साथ कुछ समस्याएँ भी उभरकर सामने आईं । वायु प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, जल स्रोतों का दूषण और यातायात भीड़ जैसी समस्याएँ 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्पष्ट होने लगी थीं । नगरीय नियोजन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया ।

इस प्रकार 1980 से 1991 का काल फरीदाबाद के औद्योगिक इतिहास में परिपक्वता, तीव्र शहरी विस्तार और सामाजिक-आर्थिक संक्रमण का चरण था । इस अवधि ने आगे आने वाले उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर के लिए आधार तैयार किया ।

उदारीकरण, वैश्वीकरण और महानगरीय रूपांतरण : 1991-2011

1991 भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक वर्ष सिद्ध हुआ । नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने देश की औद्योगिक संरचना को नई दिशा प्रदान की । फरीदाबाद, जो पहले से ही एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार विकसित कर चुका था, इस परिवर्तन का प्रत्यक्ष लाभार्थी बना । 1991 के पश्चात इसकी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक विविधीकरण, पूंजी निवेश में वृद्धि, सेवा क्षेत्र का विस्तार तथा रियल एस्टेट विकास की तीव्रता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है ।

उदारीकरण से पूर्व फरीदाबाद का औद्योगिक ढाँचा मुख्यतः लघु और मध्यम उद्योगों तथा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर आधारित था । 1991 के बाद विदेशी

निवेश के द्वार खुलने और आयात–निर्यात नीतियों में उदारता आने से स्थानीय उद्योगों को नई तकनीक, मशीनरी और वैश्विक बाजार तक पहुँच प्राप्त हुई । ऑटोमोबाइल पार्ट्स, विद्युत उपकरण, इंजीनियरिंग उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ ।

इस काल में औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण बढ़ा । 1995–96 में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 793 थी, जो 2010–11 तक बढ़कर 976 हो गई । यद्यपि यह वृद्धि संख्या की दृष्टि से अत्यधिक नहीं प्रतीत होती, परंतु उत्पादन मूल्य और निवेश में उल्लेखनीय विस्तार हुआ । मध्यम एवं बड़े उद्योगों में 2004–05 के दौरान लगभग 81 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए ।

1991 के पश्चात फरीदाबाद का संबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की अवधारणा से और अधिक सुदृढ़ हुआ । दिल्ली में भूमि की सीमित उपलब्धता और बढ़ती लागत के कारण अनेक उद्योगों और आवासीय परियोजनाओं ने फरीदाबाद की ओर रुख किया । इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में तीव्र उछाल आया । बहुमंजिला आवासीय इमारतें, निजी टाउनशिप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक केंद्रों का निर्माण इस अवधि में तेजी से हुआ ।

2001 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद की जनसंख्या लगभग 14 लाख दर्ज की गई । 2011 तक यह बढ़कर 18,09,733 हो गई । नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 79.51 प्रतिशत था, जो इसे पूर्णतः नगरीय जिला सिद्ध करता है । जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण श्रम प्रवास, सेवा क्षेत्र का विस्तार और महानगरीय सुविधाओं का आकर्षण था ।

इस अवधि में सेवा क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई । बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यवसायों का विस्तार हुआ । यद्यपि फरीदाबाद सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र नहीं बना, फिर भी एनसीआर के अंतर्गत होने के कारण आईटी–आधारित सेवाओं और आउटसोर्सिंग गतिविधियों से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ ।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सामाजिक संरचना में भी व्यापक परिवर्तन हुए । मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा और जीवनशैली में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा । निजी विद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना ने शिक्षा के स्तर को उन्नत किया । 2011 तक साक्षरता दर 81 प्रतिशत से अधिक हो चुकी थी, जिसमें महिला साक्षरता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।

नगर निगम की स्थापना (1993-94) ने प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ किया । शहरी सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क निर्माण और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए गए । हालांकि, जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता के कारण इन सेवाओं पर निरंतर दबाव बना रहा ।

उदारीकरण के बाद औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कुछ पारंपरिक लघु उद्योग बंद भी हुए, जो तकनीकी उन्नयन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ तालमेल नहीं बैठा सके । इससे श्रमिकों के बीच अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई । अनुबंध आधारित रोजगार और असंगठित श्रम की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई । श्रम बाजार अधिक लचीला तो हुआ, परंतु रोजगार सुरक्षा में कमी आई ।

पर्यावरणीय दृष्टि से यह काल चुनौतीपूर्ण रहा । औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों की संख्या में वृद्धि और निर्माण गतिविधियों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हुई । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरीदाबाद को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित किया गया । भूजल स्तर में गिरावट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या भी प्रमुख बनी रही ।

फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था का हरियाणा राज्य के कुल औद्योगिक उत्पादन में योगदान लगभग 25 से 30 प्रतिशत के बीच रहा । यह आँकड़ा इसे राज्य की औद्योगिक राजधानी के रूप में स्थापित करता है । ऑटोमोबाइल कंपोनेंट निर्माण, इंजीनियरिंग उत्पाद और विद्युत उपकरण निर्माण में इसकी विशेष पहचान बनी रही ।

इस प्रकार 1991 से 2011 का काल फरीदाबाद के लिए वैश्वीकरण, आर्थिक विविधीकरण और महानगरीय विस्तार का चरण था । इस अवधि में यह केवल एक औद्योगिक नगर नहीं रहा, बल्कि एक बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित हुआ

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

। हालांकि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय संकट और अवसंरचनात्मक दबाव जैसी समस्याएँ भी उभरीं ।

इस कालखंड ने फरीदाबाद को एक ऐसे मोड़ पर पहुँचा दिया जहाँ उसे सतत विकास, हरित औद्योगिक नीति और समावेशी शहरी नियोजन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी ।

सामाजिक संरचना, वर्गीय परिवर्तन, श्रम संबंध और नगरीय संस्कृति

1991 के पश्चात तीव्र औद्योगिक विस्तार और नगरीय प्रसार ने फरीदाबाद की सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया । यदि प्रारंभिक दशकों में यह नगर मुख्यतः शरणार्थी पुनर्वास और श्रम-आधारित उद्योगों का केंद्र था, तो 1990 के बाद यह एक बहु-वर्गीय, बहु-सांस्कृतिक और बहु-आर्थिक स्तरों वाला महानगरीय समाज बन गया । औद्योगीकरण और शहरीकरण की संयुक्त प्रक्रिया ने यहाँ वर्गीय संरचना, श्रम संबंधों, लैंगिक भूमिकाओं, आवासीय पैटर्न तथा सांस्कृतिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन उत्पन्न किए ।

फरीदाबाद की सामाजिक संरचना का पहला महत्त्वपूर्ण पहलू प्रवासन है । 1950 और 1960 के दशकों में जहाँ विभाजन के शरणार्थियों का वर्चस्व था, वहीं 1980 के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ आए । यह प्रवासन केवल अकुशल श्रमिकों तक सीमित नहीं रहा; तकनीकी और प्रबंधकीय वर्ग भी रोजगार अवसरों के कारण यहाँ बसने लगे । परिणामस्वरूप, फरीदाबाद एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक समाज में परिवर्तित हुआ । हिंदी के साथ-साथ पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी और अन्य भाषाओं का प्रयोग सामान्य हो गया ।

वर्गीय संरचना में भी स्पष्ट विभाजन उभरकर सामने आया । एक ओर उच्च और उच्च-मध्यम वर्ग था, जो बड़े उद्योगों, व्यापार, प्रबंधन और सेवा क्षेत्र से जुड़ा था । दूसरी ओर विशाल श्रमिक वर्ग था, जो लघु उद्योगों, निर्माण क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत था । इनके बीच एक विस्तृत मध्यम वर्ग विकसित हुआ, जिसमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, तकनीशियन, लघु व्यापारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी सम्मिलित थे

। यह मध्यम वर्ग नगरीय उपभोक्तावाद और आधुनिक जीवनशैली का प्रमुख वाहक बना ।

औद्योगिक विकास के साथ श्रम संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन आया । प्रारंभिक दशकों में श्रमिक और मालिक के संबंध अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष और स्थानीय थे, किंतु उदारीकरण के बाद अनुबंध आधारित रोजगार, आउटसोर्सिंग और अस्थायी श्रम की प्रवृत्ति बढ़ी । इससे श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा कम हुई और श्रम संघों की भूमिका सीमित होती गई । यद्यपि 1970 और 1980 के दशकों में श्रमिक आंदोलनों का प्रभाव था, परंतु 1990 के बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उत्पादन लागत के दबाव ने श्रम बाजार को अधिक लचीला बना दिया।

महिलाओं की भूमिका में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया । प्रारंभिक काल में महिलाएँ मुख्यतः घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, किंतु औद्योगिक विस्तार और शिक्षा के प्रसार के साथ उनकी श्रम सहभागिता बढ़ी । लघु उद्योगों, वस्त्र निर्माण, पैकेजिंग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी । महिला साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हुई, जिसने सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित किया । नगरीय परिवेश ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सहभागिता के अधिक अवसर प्रदान किए ।

आवासीय पैटर्न में भी विविधता आई । नियोजित सेक्टरों में विकसित आवासीय कॉलोनियाँ मध्यम और उच्च वर्ग के लिए थीं, जबकि श्रमिक वर्ग ने अनियोजित बस्तियों और किराए के आवासों में निवास किया । इससे सामाजिक-आर्थिक असमानता का भौगोलिक रूप स्पष्ट हुआ । नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन स्तर, सुविधाओं और अवसंरचना की गुणवत्ता में अंतर दिखाई देने लगा ।

शिक्षा संस्थानों का विस्तार सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक बना । निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना ने युवाओं को नई संभावनाएँ प्रदान कीं । शिक्षा ने न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए, बल्कि सामाजिक चेतना और राजनीतिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया । उच्च शिक्षा प्राप्त युवा वर्ग ने उपभोक्तावादी और वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाया, जिससे नगरीय संस्कृति में आधुनिकता का समावेश हुआ ।

नगरीय संस्कृति के विकास में मीडिया, संचार और उपभोक्ता बाजार की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही। 1990 के बाद केबल टेलीविजन, मोबाइल फोन और इंटरनेट के प्रसार ने सामाजिक जीवन को बदल दिया । शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और मनोरंजन केंद्रों की स्थापना ने जीवनशैली को महानगरीय स्वरूप प्रदान किया । पारंपरिक मेलों और स्थानीय सांस्कृतिक आयोजनों के साथ-साथ आधुनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होने लगा ।

हालाँकि इस तीव्र सामाजिक परिवर्तन के साथ चुनौतियाँ भी उभरीं । वर्गीय असमानता, असंगठित श्रमिकों की असुरक्षा, आवास की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव और सामाजिक समावेशन की समस्या प्रमुख रहीं । नगरीय गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एक सतत चुनौती बनी रही ।

राजनीतिक रूप से भी फरीदाबाद का महत्व बढ़ा । बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक महत्व के कारण यह राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली निर्वाचन क्षेत्र बन गया । स्थानीय निकायों की भूमिका और नागरिक भागीदारी में वृद्धि हुई, जिससे शहरी शासन की प्रक्रिया अधिक जटिल और बहुआयामी हो गई ।

इस प्रकार 1991 से 2011 के बीच फरीदाबाद केवल औद्योगिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी व्यापक परिवर्तन से गुजरा । यह नगर एक ऐसे महानगरीय समाज में परिवर्तित हुआ, जहाँ विविध वर्ग, संस्कृतियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ परस्पर क्रिया करती हैं । औद्योगिक विकास ने आर्थिक समृद्धि के अवसर प्रदान किए, परंतु साथ ही सामाजिक असमानता और नगरीय चुनौतियों को भी जन्म दिया ।

पर्यावरणीय संकट, नगरीय नियोजन, अवसंरचना और सतत विकास

फरीदाबाद का तीव्र औद्योगिक और नगरीय विस्तार जहाँ एक ओर आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर उसने पर्यावरणीय संतुलन और शहरी अवसंरचना पर गंभीर दबाव भी डाला । 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही औद्योगिक उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट, जल प्रदूषण और यातायात भीड़ की समस्याएँ उभरने लगी थीं, परंतु 1991 के बाद के तीव्र विस्तार ने इन चुनौतियों को और जटिल बना दिया । 2000 के दशक

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

तक आते-आते फरीदाबाद को प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील औद्योगिक नगरों में गिना जाने लगा ।

औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएँ, रासायनिक अपशिष्ट और धातु-आधारित कणों ने वायु गुणवत्ता को प्रभावित किया । ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंजीनियरिंग और रबर उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषकों ने शहरी वातावरण में कणिकीय पदार्थों की मात्रा बढ़ाई । वाहनों की संख्या में तीव्र वृद्धि भी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनी । दिल्ली से निकटता के कारण क्षेत्रीय वायु प्रदूषण की समस्या और गहन हो गई । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टों में फरीदाबाद को अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया, जिससे पर्यावरणीय प्रबंधन की आवश्यकता और स्पष्ट हुई ।

जल संसाधनों पर भी औद्योगिक विस्तार का प्रभाव पड़ा । भूजल का अत्यधिक दोहन, औद्योगिक अपशिष्ट का अनुचित निस्तारण और सीवेज प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था ने जल गुणवत्ता को प्रभावित किया। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई । औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपचारित जल के पुनर्चक्रण की नीतियाँ तो बनाई गईं, परंतु उनका प्रभाव सीमित रहा । तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने पेयजल की माँग को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे नगर प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव पड़ा ।

नगरीय नियोजन की दृष्टि से फरीदाबाद का प्रारंभिक विकास सेक्टर आधारित मॉडल पर हुआ था, जिसने इसे एक व्यवस्थित ढाँचा प्रदान किया । परंतु प्रवासन की तीव्रता और अनौपचारिक आवासीय बस्तियों के विस्तार ने इस नियोजन मॉडल को चुनौती दी । नियोजित सेक्टरों के अतिरिक्त अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का विस्तार हुआ, जहाँ आधारभूत सुविधाएँ सीमित थीं । इससे शहरी असमानता और अवसंरचनात्मक असंतुलन स्पष्ट हुआ ।

परिवहन अवसंरचना भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरी । राष्ट्रीय राजमार्ग से संपर्क और दिल्ली की निकटता ने यातायात को तीव्र बनाया । निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण सड़कों पर भीड़ बढ़ी और प्रदूषण में वृद्धि हुई । सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अपेक्षाकृत सीमित रही, जिसके कारण यातायात प्रबंधन जटिल हुआ । 2000 के दशक में सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण जैसे कदम उठाए गए,

किंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक गतिविधियों के कारण यह पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या भी गंभीर रही । औद्योगिक कचरे और घरेलू अपशिष्ट के पृथक्करण तथा वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था सीमित थी । नगर निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयास किए गए, किंतु जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्तावादी जीवनशैली के कारण कचरे की मात्रा निरंतर बढ़ती रही ।

हरित क्षेत्र की उपलब्धता में भी कमी देखी गई । औद्योगिक इकाइयों और आवासीय परियोजनाओं के विस्तार ने खुले स्थानों और कृषि भूमि को कम कर दिया । यद्यपि कुछ पार्क और हरित पट्टियाँ विकसित की गईं, परंतु उनका अनुपात बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप नहीं था । पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए, किंतु उनका प्रभाव सीमित रहा।

सतत विकास की अवधारणा 2000 के दशक में नीति-निर्माण के केंद्र में आने लगी । औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों को कठोर किया गया । अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्थापना, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और पर्यावरणीय निगरानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए । साथ ही, शहरी नियोजन में हरित क्षेत्र और सार्वजनिक स्थानों को बढ़ाने पर बल दिया गया ।

सामाजिक दृष्टि से पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभाव निम्न आय वर्ग पर अधिक पड़ा । अनौपचारिक बस्तियों में स्वच्छ जल और स्वच्छता की सुविधाओं का अभाव स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को बढ़ाता रहा । इससे शहरी विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन की आवश्यकता स्पष्ट हुई ।

फरीदाबाद का अनुभव यह दर्शाता है कि तीव्र औद्योगीकरण और नगरीकरण यदि पर्यावरणीय संतुलन के साथ न हो तो दीर्घकालीन समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है । हरित औद्योगिक नीति, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन की वैज्ञानिक व्यवस्था और जल संरक्षण की दीर्घकालिक रणनीति - ये सभी उपाय भविष्य के सतत विकास के लिए अनिवार्य हैं ।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

इस प्रकार, 1991 से 2011 के बीच फरीदाबाद का पर्यावरणीय और अवसंरचनात्मक परिदृश्य यह संकेत देता है कि औद्योगिक प्रगति के साथ नियोजित और सतत विकास की रणनीति आवश्यक है ।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, तुलनात्मक विश्लेषण, नीति–सुझाव और समग्र निष्कर्ष

फरीदाबाद के 1947 से 2011 तक के विकास का विश्लेषण केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत में औद्योगीकरण और शहरीकरण की प्रक्रियाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण अध्ययन भी है । इस अंतिम भाग में इस संपूर्ण विकास यात्रा को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से समझने, अन्य एनसीआर नगरों से तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने तथा भविष्य के लिए नीति–सुझाव देने का प्रयास किया गया है ।

औद्योगीकरण के सैद्धांतिक संदर्भ में यदि देखा जाए तो फरीदाबाद का विकास "आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण" (Import Substitution Industrialization) की प्रारंभिक नीति से जुड़ा रहा । स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिकता दी । फरीदाबाद में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना इसी नीति का परिणाम थी । इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने का प्रयास किया गया ।

नगरीकरण सिद्धांतों की दृष्टि से फरीदाबाद का विकास "योजनाबद्ध शहरीकरण" (Planned Urbanization) का उदाहरण है । प्रारंभिक दशकों में सेक्टर आधारित मॉडल अपनाया गया, जिसने इसे एक सुव्यवस्थित संरचना प्रदान की । परंतु समय के साथ प्रवासन और अनौपचारिक बस्तियों के विस्तार ने "स्वत:स्फूर्त नगरीकरण" (Spontaneous Urbanization) की प्रवृत्ति को भी जन्म दिया । इस प्रकार फरीदाबाद का अनुभव योजनाबद्ध और अनियोजित–दोनों प्रकार के शहरी विस्तार का मिश्रित स्वरूप प्रस्तुत करता है ।

वैश्वीकरण सिद्धांत के संदर्भ में 1991 के बाद का काल अत्यंत महत्वपूर्ण है । उदारीकरण के पश्चात विदेशी निवेश, तकनीकी उन्नयन और वैश्विक बाजार से जुड़ाव ने फरीदाबाद की औद्योगिक संरचना को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया । परंतु इसके साथ ही

असंगठित श्रम, अनुबंध आधारित रोजगार और सामाजिक असमानता की समस्याएँ भी उभरीं । यह स्थिति "वैश्विक पूंजी और स्थानीय समाज" के बीच अंत:क्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है ।

तुलनात्मक दृष्टि से यदि फरीदाबाद की तुलना गुरुग्राम और नोएडा जैसे एनसीआर नगरों से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि फरीदाबाद का विकास औद्योगिक आधार पर अधिक केंद्रित रहा, जबकि गुरुग्राम और नोएडा में सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का वर्चस्व अधिक रहा । गुरुग्राम में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉर्पोरेट कार्यालयों का तीव्र विस्तार हुआ, जबकि फरीदाबाद ने विनिर्माण (manufacturing) क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए रखी । यह अंतर दर्शाता है कि एनसीआर के भीतर भी प्रत्येक नगर की विकास दिशा और संरचना भिन्न रही।

फरीदाबाद का योगदान हरियाणा के औद्योगिक उत्पादन में लगभग एक-चौथाई से अधिक रहा है । ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंजीनियरिंग उपकरण और विद्युत मशीनरी निर्माण में इसकी विशेष पहचान बनी रही । इस दृष्टि से यह हरियाणा की औद्योगिक राजधानी के रूप में स्थापित हुआ ।

हालाँकि तीव्र औद्योगीकरण और नगरीकरण ने अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न कीं । पर्यावरणीय प्रदूषण, भूजल संकट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात दबाव और सामाजिक असमानता प्रमुख समस्याएँ रहीं । इन समस्याओं से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास के साथ सतत विकास की रणनीति का अभाव दीर्घकालीन संकट उत्पन्न कर सकता है ।

भविष्य के लिए नीति-सुझावों में हरित औद्योगिक नीति का निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण मानकों का कठोर पालन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विस्तार, जल संरक्षण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा सस्ती आवास नीति का विकास आवश्यक है । इसके अतिरिक्त कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं ।

शहरी शासन को अधिक सहभागी और पारदर्शी बनाना भी अनिवार्य है। नगर निगम, विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर दीर्घकालीन

मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता दी जाए ।

निष्कर्ष :

समग्र रूप से देखा जाए तो 1947 से 2011 तक फरीदाबाद का विकास भारतीय औद्योगीकरण और शहरीकरण की व्यापक प्रक्रिया का एक सजीव उदाहरण है । यह नगर पुनर्वास केंद्र से औद्योगिक महानगर तक की यात्रा का साक्षी रहा है । सरकारी नीतियाँ, सार्वजनिक और निजी निवेश, श्रम प्रवास, भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की निकटता–इन सभी कारकों ने इसके विकास को आकार दिया ।

फरीदाबाद की कहानी केवल आर्थिक प्रगति की कथा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, वर्गीय पुनर्संरचना, सांस्कृतिक विविधता और पर्यावरणीय चुनौतियों की भी कहानी है । यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि औद्योगिक विकास और नगरीय विस्तार को दीर्घकालिक रूप से सफल बनाने के लिए सतत विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन की रणनीति अनिवार्य है ।

संदर्भ

1 जैन, एल० सी० (1976). द सिटी ऑफ होप : द फरीदाबाद स्टोरी. नई दिल्ली : एलाइड पब्लिशर्स.

2 यादव, के० सी० (1996). हरियाणा का इतिहास. कुरुक्षेत्र : हरियाणा साहित्य अकादमी.

3 यादव, के० सी० (2002). मॉडर्न हरियाणा : हिस्ट्री एंड कल्चर. नई दिल्ली : मनोहर पब्लिशर्स.

4 फौजदार, रामफूल सिंह (2008). हरियाणा का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास. रोहतक : सूर्य प्रकाशन.

5 मलिक, बी० एस० (2010). हरियाणा का आर्थिक विकास. चंडीगढ़ : हरियाणा ग्रंथ अकादमी.

6 सिंह, आर० एस० (2005). हरियाणा में औद्योगीकरण. नई दिल्ली : रावत पब्लिकेशन्स.

7 सभरवाल, गोपा (2007). इंडिया सिंस 1947. नई दिल्ली : पेंगुइन बुक्स इंडिया.

8 भारत की जनगणना (1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011). नई दिल्ली : भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त.

9 हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण (2005–06; 2015–16). चंडीगढ़ : वित्त विभाग, हरियाणा सरकार.

10 हरियाणा सांख्यिकीय सार (1992; 2010; 2020). चंडीगढ़ : अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हरियाणा सरकार.

11 जिला उद्योग केंद्र, फरीदाबाद (2011). फरीदाबाद जिला औद्योगिक प्रोफाइल. फरीदाबाद : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा.

12 नगर निगम फरीदाबाद (2018). शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना प्रतिवेदन फरीदाबाद : नगर निगम.

13 हुडा (अब एच.एस.वी.पी.) (2017). फरीदाबाद विकास योजना रिपोर्ट. चंडीगढ़ : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण.

14 गुर्जर, आर॰ के॰ (2012). हरियाणा का सांस्कृतिक परिदृश्य. रोहतक : हरियाणा अध्ययन केंद्र.

15 शर्मा, एस॰ पी॰ (2014). उत्तर भारत में शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ. नई दिल्ली : अटलांटिक पब्लिशर्स।